भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण **विभाग**
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3887
12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: छोटे और सीमांत किसानों के लिए एग्री स्टैक का लाभ

3887. श्री राजकुमार चाहरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एग्री स्टैक पहल छोटे और सीमान्त किसानों को लाभ प्रदान करने में सरकार के लिए किस प्रकार सहायक होगा;

(ख) क्या एग्री स्टैक फ्रेमवर्क के माध्यम से किसानों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार ने सितंबर 2024 में डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी थी। इस मिशन का उद्देश्य देश में एक सुदृढ़ डिजिटल कृषि इकोसिस्टम के निर्माण हेतु एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (केडीएसएस) और एक व्यापक सॉइल फर्टिलिटी एवं प्रोफ़ाइल मैप सहित कृषि के लिए एक डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का निर्माण करना है। यह नवीन किसान-केंद्रित डिजिटल समाधानों को सक्षम बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि फसल संबंधी विश्वसनीय जानकारी सभी किसानों तक शीघ्रता से पहुँचे। एग्रीस्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन प्रमुख रजिस्ट्री या डेटाबेस शामिल हैं, अर्थात् भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र, बोई गई फसल रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री, जिनका निर्माण और रखरखाव राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

किसान रजिस्ट्री किसानों के जनसांख्यिकीय विवरण, भूमि जोत और बोई गई फसलों पर व्यापक और उपयोगी डेटा प्रदान करती है, जिससे किसान ऋण, बीमा, खरीद आदि जैसे लाभ और सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण कर सकते हैं। यह राज्यों को ऐसे समाधान तैयार करने में भी सक्षम बनाती है जो किसानों के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था तक पहुँच प्रदान करते हैं, जैसे कि इनपुट और उपज की विश्वसनीय तरीके से ऑनलाइन खरीद और बिक्री। डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) प्रणाली द्वारा समर्थित बोई गई फसल रजिस्ट्री प्रत्येक कृषि भूखंड के लिए सटीक, वास्तविक समय की फसल क्षेत्र की जानकारी प्रदान करती है।

एग्रीस्टैक सरकारों को किसान-केंद्रित डिजिटल सेवाएं विकसित करने, विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के कार्यान्वयन में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करने और किसानों को परेशानी मुक्त और समावेशी लाभ वितरण में सहयोग करता है।

i. जनसमर्थ (एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो क्रेडिट-लिंक्ड सरकारी योजनाओं को जोड़ता है) को एग्रीस्टैक के साथ एकीकृत किया गया है ताकि किसानों को परेशानी मुक्त और कागज़ रहित किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्राप्त करने में मदद मिल सके।

ii. एग्रीस्टैक कुशल और पारदर्शी एमएसपी-आधारित खरीद की सुविधा प्रदान करता है। इसके तहत फसल-आधारित एसएमएस संचार के माध्यम से, सरकारी एजेंसियों द्वारा दलहन उत्पादक किसानों से लक्षित और पारदर्शी खरीद पहुँचाने में मदद की है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदी गई फसलों के सत्यापन में मदद के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण को उत्तर प्रदेश की खरीद प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।

iii. सॉइल हेल्थ कार्ड सेवाओं में सटीक सॉइल सेंपल संग्रह के लिए किसान आईडी और भू-संदर्भित ग्राम मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है।

iv. डिजिटल फसल सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित फसल आंकड़ों से न केवल सरकार को उपग्रह फसल मानचित्रों की सटीकता में सुधार करने के लिए रिमोट सेंसिंग संकेतों को अधिक सटीक बनाने में मदद मिली है, बल्कि इससे फसल उत्पादन का त्वरित अनुमान लगाना भी संभव हुआ है।

****